होंगे कि जब तक यह कानून बनेगा उस दिन तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। पिछले 8-10 सालों से इस देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार जो सोचती है, वह कर नहीं पा रही है। इच्छा शक्ति का अभाव हो गया है सरकार में और दूसरा ईमानदारी नहीं रह गई है। जो जिम्मेदारी ली है उत्पादन करने की, वितरण करने की और पारेषण करने की, यह लोग अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। आज सरकार को इन सब बातों पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। हम स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, हमारी आजादी को 50 साल हो गये हैं लेकिन सब गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। मंत्री जी आंकड़े बतलाएंगे कि देश में कितने गांवों का अब तक विद्युतीकरण किया गया। लाइनें खींच दी गई विद्युतीकरण के नाम पर, खम्भे गाड़ दिये गए हैं, लेकिन गांव में बिजली नहीं है। (व्यवधान)

मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी: दिल्ली में भी बिजली नहीं है।

†شری عبید اللہ خان اعظمی: دہلی میں بھی بجلی نہیں ہے

श्री ईश दत्त यादव: महोदय, ठीक कह रहे हैं ओबैदुल्ला खान साहब कि दिल्ली में भी बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था।

6.00 P.M.

दिल्ली में सबसे ज्यादा बिजली की चोरी हो रही है। यह माननीय ऊर्जा मंत्री की भी जानकारी में होगा। लेकिन माननीय ऊर्जा मं . जी के लिए भी दुष्कर होगा। यहां चोरी कोई साधारण आदमी नहीं कर रहा है। झुग्गी झोपडी में रहने वाला आदमी चोरी नहीं कर रहा है ....(समय की घंटी)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): ईश दत्त यादव जी, आपके लिए 7 मिनट थे और आप 7 मिनट बोल चुके हैं। 6 बजे हमारी लिस्ट आफ बिजनेस के मुताबिक हाफ एन आवर शुरू करना है। आप एकाध मिनट में खत्म कर दें।

श्री ईश दत्त यादव: ठीक है, उपसभाध्यक्ष जी, आपका जो आदेश है उसका मैं पालन करूंगा।

उपसभाध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम: आपका समय तो हो चुका है। आप आधे-एक मिनट में खत्म कर दें।

श्री ईश दत्त यादव: ठीक है, उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

उपसभाध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम: वरना आप बाद में बोल लें हाफ एन आवर डिसक्शन के बाद, अगर बहुत कुछ बोलना है।

श्री रामदास अग्रवाल: दिल्ली के अंधेरे पर बोल दीजिए।

श्री ईश दत्त यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आप सब लोगों की जो राय है वह मेरी भी राय है। संजय निरूपम जी और सब लोग कह रहे हैं कि इस देश के अंदर बिजली की बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है। सभी लोगों की यही राय है। माननीय मंत्री जी आप विधेयक ले आए हैं मैं आपसे पुन: निवेदन करूंगा हमारी कोई ऐसी मंशा है कि आपकी सरकार चले, आप रहें और अगर आप रह जाते हैं तो मेरे इन सुझावों पर आप गंभीरता से विचार करें।

इस बिल को आप वापस ले लीजिए। उत्पादन, पारेषण और वितरण, इन तीनों के बारे में एक कंप्रीहेंसिव बिल आप लाइए। अगर तीनों के बारे में एक कम्प्रीहेंसिव बिल आप ले आएंगे तो सही मानों में देश में विद्युत की समस्या हल हो सकती है और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of answer to starred Question No. 281 Given on 6th July, 1998 Regarding Piling up of Steel at S.A.I.L.

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या 281 जब यहां सदन में प्रस्तुत हुआ था तो सभापति महोदय ने आधे घंटे के डिसकशन के लिए अनुमति दी थी। मैं उसी संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष जी, इस समय स्टील इंडस्ट्री पर काले बादल मंडराए हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से डिमांड में बहुत कमी होने के कारण

माल का उठाव नहीं है। पिछले वर्षों में कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाने के कारण बाजार में कंपीटिव प्राइसेज में बेचना संभव नहीं हो रहा है। इम्पोर्टिड मेटीरियल उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत में आ गया है। उससे भी प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है। हमारे यहां पर स्टील प्लांट्स के एक्सपेन्शन हुए। हम सोचते थे कि स्टील प्लांट्स का एक्सपैंशन 3-5 साल में पूरा होगा। उसके बजाए वे 5 से 10 साल के बाद पूरे हुए। हम सोचते थे कि स्टील प्लांट्स के एक्सपैंशन में दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट का एक्सपैंशन होगा, माडर्नाइजेशन होगा, उत्पादन बढ़ेगा और कीमतें कम होंगी। उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ कास्ट आफप्रोडकशन कम होना चाहिए। लेकिन महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टील मंत्रालय, "सेल" ये सब होने के बावजूद हमारे देश की इंडस्ट्री की यह हालत हो गयी। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दुर्गापुर स्टील प्लांट का एक्सपैंशन, माडर्नाइजेशन 2068 करोड़ रुपए के लिए तय किया गया था, जब प्लान किया गया था। जब माडर्नाइजेशन कंप्लीट हुआ तो उस समय इसकी कास्ट आई 4870 करोड़ रुपए। महोदय, इसी प्रकार से राउरकेला स्टील प्लांट की 2400 करोड़ रुपए के बजाए जब प्लान कंप्लीट होगा तो कास्ट आएगी 5112 करोड़ रुपए। हमारे यहां पर कास्ट बढ़ती जा रही है। एक्सपैंशन में ओवर रन हो रहा है टाइम और कास्ट में।

अब अगर आपको दुनिया के दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करनी है आज की उदारीकरण की नीति के समय में, तो आप इन सारी अपनी कमियों के आधार पर दुनिया के देशों से कैसे कम्पीट करेंगे? दूसरी जगहों पर स्टील प्लांट में टोटल स्टील प्लांट नीचे नींव से ले करके और स्टार्टिंग प्वायंट तक तीन से पांच साल से ज्यादा समय कहीं नहीं लगाता, हमारे यहां पर माडर्नाइज़ेशन में 5 से 10 साल का समय लगता है, तो आप कैसे कंपीट करेंगे? जो हालत आज होनी थी वहीं हुई है। इसमें आपके पास कोई च्वाइस नहीं है। मुझे हमदर्दी सिर्फअपने मंत्री जी से है क्योंकि वह बेचारे अभी आए हैं। इनके कार्यकाल में न तो कोई स्टील प्लांट लगा, न इनके कार्यकाल में कोई स्टील प्लांट का माडर्नाईज़ेशन हुआ। इनको तो अब 'करे कोई और भरे कोई' वाला हिसाब है। इनको जवाब देना पड़ेगा। पिछले जो महानुभाव रहे होंगे उनके कार्यक्रमों के द्वारा जो ढील बरती गई, जो उसमें कठिनाइयां पैदा की गईं, कुछ जान-बूझ कर हुई कुछ बिना जान-बुझ कर हुई होंगी, लेकिन हुई जरूर, उसके कारण आज स्टील इंडस्ट्री की हालत खराब है। यह हम सब को साफ-साफ दिखाई देता है और यह क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए हॉफएन ऑवर डिसकशन इस पर रखा गया था।

महोदय, मैं केवल दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि स्टील इंडस्ट्री का नफा अर्थात् प्राफिट 1997-98 में 134 करोड़ रह गया जो कि 1996-97 में 515 करोड़ था और इसके पहले वर्ष में 1995-96 में यह 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा था। इसी से हम देख सकते हैं कि इन पिछले तीन वर्षों में हमारे स्टील प्लांट्स की दुर्दशा किन कारणों से हुई। उनकी व्याख्या तो हमारे मंत्री महोदय करेंगे, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले समय में जो मंदीवाड़ा इस देश में आया है आर्थिक क्षेत्र में और कंस्ट्रकशन के क्षेत्र में, स्टील का उत्पादन बढ़ा लेकिन स्टील की खपत कम हो गई, और उसी के कारण स्टील की इंडस्ट्री में इस प्रकार की दुर्दशा पैदा हुई। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह दुर्दशा तो हुई, लेकिन इस दुर्दशा को रोकने के लिए हमारी सरकार क्या प्रयास करने वाली है जिससे कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर इस समय जो संकट के बादल छाए हैं हम उसको हटा सकेंगे, यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है जो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

महोदय, मैं दूसरी बात और जानना चाहता हूं कि इस समय उदारीकरण नीति के आधार पर इंपोर्ट हो रहा है और दुनिया के बाजार से कंपीट करना पड़ता है और उसमें हमारा स्टील का जो उद्योग है शायद उनका सामना नहीं कर सकेगा। तो क्या इस प्रकार की परिस्थिति बनी रहेगी, इंपोर्टेड स्टील सस्ता रहेगा और भारत का पैदा किया हुआ स्टील महंगा रहेगा? और जब बाज़ार में बेचने जायेंगे तो आपको अपनी प्राइस से, कास्ट प्राइस से कमती में या जो प्राइस आपने फिक्स की है उससे कमती में आपको बेचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा? क्योंकि मैं जानता हूं कुछ उदाहरण सामने आए हैं कि जब सेल ने अपने मैटीरियल को कंसैशनल रेट पर मार्केट में बेचा है। यह उनकी मजबूरी हो सकती है। यह उनकी और मार्केट की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन यह परिस्थिति इंपोर्टेड स्टील के आने के कारण पैदा हुई है। मैंने पहले भी एक बार, जब मैं सदन में वित्त विधेयक पर बोल रहा था, तो उस समय भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे लिए आज यह आवश्यक है कि हम दो बातों पर ध्यान दें। हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया जो हमने अपनी इंडस्ट्री में लगाया है उसको हम बर्बाद होने से बचाएं। केवल बाहर से माल आकर इस देश में बिके, सस्ता बिके और हमारा माल महंगा हो और बिके नहीं। बिके तो फिर कास्ट से कमती में बेचना पड़े, नुकसान उठा कर बेचना पड़े तो हमारे देश के उद्योग की क्या हालत होगी, वह हम सब अपनी आंखों से इस समय देख रहे है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने

एंटी डंपिंग ड्यूटी अथवा इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा कर इस प्रकार से इस नुकसान से, देश को बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? किए हैं, तो आप कृपा कर बताने का कष्ट करें।

दूसरा एक और सवाल बीच में खड़ हुआ था कि इस उद्योग में 6 लाख लोग काम करते हैं। मेरी जानकारी में यह बात आई है कि इसमें ओवर स्टॉफिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद चार लाख लोगों से काम चल सकता है। इसमें दो लाख लोग ज्यादा हैं, जबकि हमारे यहां पर दो लाख आदमियों को आप किसी प्रकार से हटा नहीं सकते, आप किसी को अनएंप्लोइ नहीं कर सकते और न मैं कोई सुझाव दे रहा हूं कि आप उनको नौकरी से हटाएं, लेकिन यह जो समस्याएं आपके सामने हैं, आप इनका क्या समाधान करेंगे? क्या नुकसान उठाते चले जाएंगे क्योंकि स्टील डिपार्टमेंट ने जो फिगर्स दिए हैं, यह हमारे लिए आकर्षक भी हैं और बहुत पश्चाताप के भी हैं।

"Investment per tonne of steel in SAIL, vice-versa other steel producers in Asia and its investment performance."

महोदय, इस संबंध में हम स्टील का नेट प्रोफिट टू इनवेस्टमेंट देखें तो वर्ष 1996-97 में यह 2.9 परसेंट है जबकि टिस्को का रिटर्न 7.7 परसेंट है। यहीं पर गैप स्पष्ट दिखाई देता है कि स्टील 2.9 परसेंट पर काम करता है जबकि टिस्को का रिटर्न 7.7 परसेंट है। इसी से अंदाजा लगता है कि सेल में किस प्रकार की इन-एफीसिएंसी से काम हो रहा होगा और किस प्रकार से उसमें कॉस्ट बर्डन बढ़ता जा रहा है। यह मेरे प्रश्न का तीसरा भाग है। चौथा प्रश्न मंत्री महोदय के सामने मैं यह रखना चाहता हूं कि कॉस्ट ओवर रन या टाइम ओवर रन जो होता है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आप कहेंगे कि आप की नहीं है क्योंकि आप उस वक्त मंत्री नहीं थे, जो और सेल की अथॉरिटीज होंगी, वह कहेंगे कि मैं तो चैयरमेन दो साल से हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेक्रेटरी कहेगा कि मैं दो साल पहले सेक्रेटरी बना हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब इसमें कॉस्ट रन जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी पिछले और उसके पिछले पर जाती है। महोदय, इस तरह का प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया है कि क्या कहीं कोई सीमा तय की जाएगी? क्या कॉस्ट ओवर-रन और कैपिटल ओवर रन इसी प्रकार होता रहेगा? महोदय, न केवल स्टील के बल्कि उदाहरण के तौर पर देखें तो बहुत सारे उद्योग मिल जाएंगे जहां कि इस तरह के कारण की वजह से उद्योग संकट में आ गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्टील इंडस्ट्री को इस संकट से बचाने के लिए जो पिछली कार्यवाहियां हुई हैं या कॉस्ट ओवर-रन हुआ है, इ स संबंध में जानकारी देंगे? वह किस कारण से हुआ शायद उसकी जानकारी तो आपको मिल गयी होगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई इफेक्टिव एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं? क्या जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को इस प्रकार से कॉस्ट ओवर-रन कर दिया है, कैपिटल ओवर-रन कर दिया है.....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): यहां भी टाइम ओवर रन हो जाएगा।

श्री रामदास अग्रवाल: क्या उन लोगों के ऊपर आप कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सब को "स्कॉट फ्री" कर दिया जाना चाहिए? कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पांसिबिलिटी और कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? महोदय, बिना एकाउंटेलिबिलिटी के ही आज इस देश में यह दुर्दशा हुई है।

इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में बड़ी गंभीरता से विचार करें और जो लोग, मानो इस में दोषी पाए जाते हैं, उन के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भी सरकार को कमर कसनी पड़ेगी ताकि भविष्य में कोई भी उद्योग-धंधा केवल इस कारण से अपनी उत्पादन क्षमता को खत्म न कर दे या अपनी कॉस्ट को बढ़ा न दे।

महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे इन कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। निरूपम जी ने यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, मैं उन का आभारी हूं और आप ने मुझे समय दिया, उस के लिए मैं आप को भी धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI MD. SALIM) Now, Mr. Minister's reply.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, let all questions be asked and then the hon. Minister may reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): No it is not the practice here. Mr. Minister you may reply, otherwise there will not be questios, there will be speeches.

THE MINISTER OF STEEL (SHRI NAVEEN PATNAIK): Sir, before I reply to the hon. Member's question, I may tell you what the new Government has been trying to make the future of steel sector more

optimistic. It is the policy of this Government that a great deal of work be done in infrastructure. When it comes—it will be the thrust of this Government—you will see that a great deal of steel will be consumed in the infrastructure sector—oil refinaries, bridges, ports, thermal stations, and factories, in which steel is consumed.

Also, Sir, this Government intends to build two million houses both in the urban and in the rural sector. In this area too a great deal of steel will be consumed. It is a push that my Ministry is trying to make to find new markets for steel in the rural areas which have such a vast capacity or vast rural population ...*(Interruption)*...

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, आप मंत्री महोदय को निर्देश दें कि स्पीच नहीं देना है। समय बहुत कम है और सवाल बहुत ज्यादा हैं। यह जो भाषण दे रहे हैं मंत्री महोदय, वह हम सब जानते हैं, हमारे पास इसकी सारी जानकारी है कि बहुत सारे घर बनाने हैं, यह करना है, वह करना है। यह स्टील का इस्तेमाल कहां होना है, कहां नहीं होना है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। जो सवाल माननीय रामदास अग्रवाल जी ने उठाए हैं, उन सवालों का ही आप जवाब दें ताकि हम फिर आगे अपने सवाल रखें।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मंत्री जी यह सारी जानकारी दे रहे है, रामदास अग्रवाल जी नें जो पाइंट उठाए हैं, उसके ऊपर ही वह रेप्लाई दे रहे हैं। इसके बाद आप जो प्रश्न करेंगे, उसके ऊपर मंत्री जी आपको जवाब देंगे। बोलिए, मंत्री जी।

You have to be brief because this is half-an-Hour Discussion.

श्री संजय निरूपम: सवाल वह नहीं है। ....(व्यवधान)....

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, I will be brief. The Department is ..*(Interruption)*...

AN HON. MEMBER: There can be a time over-run also.

SHRI NAVEEN PATNAIK: The Department of steel is doing its best to ensure that the temporary slow-down in demand does not imperil the long-term picture. I mentioned some of the important initiatives taken by my Ministry after March, this year. First we took up the import Duty rationalisation with the Ministry of Finance. The response has been positive. The Budget for the current year has increased, The import duty, across the board, by 4 per cent.

This will give many industries—including the steel industry a more of a level-playing field.

The import duty differenctial on hot roll coils and cold roll coils has been re-introduced. This will help our hot roll coil producres. There are some other factors in this.

Secondly, at our instance, rates for available benefits under the Duty Entitlement Pass Book, which is better known as the DEPB, Scheme have been revised upwards for many items of iron and steel. We have also taken up with the Ministry of Commerce issues related to dumping of steel from several neighbouring countries.

Thirdly, we requested the Railways to desist from raising freight rates. It is gratifying to note that the industry has been spared from any general freight hike during the current year. We have also taken up the issue of high railway freight on the KK line and the Railways are looking into it.

Fourthly, we are addressing the demand side of the current problem. A national campaign to incerase steel consumption has been launched. To promote exports, a Steel Exporters Forum has been established. In the last financial year 1997-98, the nation exported three million tons of steel. That shows that we are global players and we are certainly putting more of a thrust both in the Ministry and also as facilitators of the steel industry; that more of a thrust should be given for export so that by the year 2001-2002 AD we should be able to double our export to six million tons thereby earning valuable foreign exhcnage for our nation.

DR. BIPLAB DASGUPTA: How much are we importing?

SHRI NAVEEN PATNAIK: Certainly, itis not anything near three million tons.

DR. BIPLAB DASGUPTA: What is the amount? *(interruption)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You will have a chance to put questions. First, let the Minister conclude.

SHRI NAVEEN PATNAIK: We are importing about 1-1/2 million tons. We are importing only half of what we are exporting. Sir, I hope you see the difference. During the last finaical year, the domestic market production of steel has been solid.

It has been put at 23 million tonnes. Sir, when we began it in the First Five-Year Plan, we produced slightly more than one million tonnes only. Today, our nation can be proud of the fact that we are the tenth largest steel producer in the world.

Now, if I may reply to some of the hon. Member's questions; the hon. Member asked about the Durgapur Steel Plant. The hon. Member mentioned about certain complaints and about the cost overrun and the time overrun of the Durgapur Steel Plant.

The hon. Member himself mentioned. I, too, would like to underline the fact that as far as the cost overrun and the time overrun in respect of both the Durgapur and the Rourkela Steel Plants is concerned, it is something which has been inherited by our Government. These have been going on for quite some time, as the hon. Member knows. In regard to the details of the cost and the time overrun, the report of the Comptroller and Auditor-General has already been placed in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha during this session.

Also, Sir, I would like to mention about the methods that are now being adopted to try and monitor the matters concerned with our integrated steel plants. The present Government is trying to reduce the delays so that the benefits of our work on modernisation flow easily.

The monitoring is done by the Managing Directors of the steel plants on a day-to-day basis. Then, the Chairman, SAIL, does the monitoring on a monthly basis. The Department of Steel does the monitoring on a quarterly basis; and, at my level, again, on a quarterly basis. The Department of Programme Implementation also comes into the picture. It goes still further. It goes to the Cabinet Secretariat and then to the Prime Minister's Office. These targets are set on, mainly, a monthly basis, as you can see.

Thank you, Sir.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: If there are too many co-ordinators, they would spoil the thing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Minister, you need not reply to him.

श्री रामदास अग्रवाल: सर, मेरे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं आया।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अभी जवाब देंगे वह।

श्री रामदास अग्रवाल: सर, मैंने पूछा था.....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): दूसरों को भी बोलने दें आप।

श्री रामदास अग्रवाल: मैं मना नहीं कर रहा हूं, साहब, उनका तो नाम है उसमें, उनको तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, आप पहले बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Jibon Roy, please.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to put on record that the entire steel industry is really in a crisis. It is not just the SAIL. The entire steel industry is in a crisis. It is because of liberalisation and globalisation. In fact, the hon. Member should support me in opposinig liberalisation and globalisation. The thing is that, during his period, the excise duty has increased from ten to fifteen per cent.

SHRI RAMDAS AGARWAL: Mr. Jibon Roy, you were in the Government when this policy was continued, after the Narasimha Rao Government. You were there. You should have opposed it at that time.

SHRI JIBON ROY: The excise duty increased from ten per cent to fifteen per cent. On the other hand, the customs duty went down from eighty-five per cent to twenty-five per cent. During the last eight years, the capacity increased by ten million tonnes, but the demostic demand increased at the rate of 0.6 per cent.

Obviously, there is crisis. There is a serious crisis. I would suggest to the Government to see that all the producers are brought together

and some understanding is reached among them on the price front as well as on the marketing front. If no understanding is reached, I suggest that you flood the steel market with the products of SAIL. Let them face the music. The only way is that they should work jointly on the question of marketing as well as on the question of pricing. Otherwise, the stock would go on pilling up. When cutthroat competition is there, this 1.4 million tonnes could become two million tonnes and even three million tonnes. Stocks would pile up in our stockyards. Therefore, you should take steps to protect SAIL.

Secondly, three million tonnes are coming from outside, if you take the OGL and the legal route together. Therefore, the Commerce Ministry should initiate the procedure so that anti-dumping duty is imposed on the people who dump steel into the country. What steps have been taken in this regard? The hon. Minister may kindly explain.

Thirdly, Sir, now there is a competition between cement and steel also. In an area where steel could be used but cement should not be used, cement is being used. Railway sleepers, for example. Cement is used for railway sleepers. You cannot keep obsolete sleepers on the side of the rails. It is becoming a jungle of cement. New sleepers have been discovered. You have to take it up with the Railways to see that more and more sleepers are used.

Fourthly, here in Delhi we are building a Memorial House. We wanted to use steel, and we brought a plan from the International Steel Corporation. Urban Development Ministry of the Government of India has rejected it. It does not know that steel is used in construction, in building in a bigger way and a massive way throughout the world. The CPWD norms are the 18th century norms. You have to take it up with the Urban Development Ministry so that steel is used in a bigger way. You can use cement only once, but steel can be alloyed, recycled and re-used. These steps should be taken.

So far as Durgapur and Rourkela are concerned, one thing is that—I come from Durgapur—because of the break-up of the Soviet Union, there were constraints, and there were many difficulties. Because of that, no material was coming from the Soviet Union after its break-up. Otherwise, the development work at Durgapur was much more rapid this time than on previous occasions. But there are serious complaints of corruption, laundering of money, both in Rourkela and Durgapur.

In reply to Rajya Sabha Starred Question No. 371 which did not come up, you have agreed:

> "Complaints/references received in the Ministry alleging irregularities in respect of modernisation projects at Durgapur Steel Plant and Rourkela Steel Plant of SAIL are duly examined in consultation with concerned authorities. As on date, no formal enquiry has been ordered by Ministry of Steel in this regard."

I request you to assure us that steps will be taken, that an enquiry will be made and that whoever is responsible for corruption, would be booked.

That is all. Thank you.

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, इसी संदर्भ में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपको बोलने दिया जाएगा। आपको पहले भी 20 मिनट मिले थे। फिर मिलेगा आपको समय। अभी दवे जी को बोलने दीजिए।

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, would you like me to answer the hon. Member's question now or would you like me to wait till other Members spoke?

SHRI JIBON ROY: You take them up all together.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय रामदास जी ने और जीवन रॉय जी ने सारी बातें यहां बताई हैं और बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं। निरुपम जी ने जो सवाल उठाया था, उसी से यह डिबेट आगे चली है। मैं मानता हूं कि स्टील इंडस्ट्रीज अभी घाटे में चल रही है और उनका जो कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए, वह घट रहा है और मुनाफा भी घट रहा है लेकिन साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर में जो इंडस्ट्री है, वह अच्छी तरह से चल रही है, आगे जा रही है। इस बारे में

माननीय रामदास अग्रवाल जी ने कई सवाल पूछे थे और मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया है।

श्री संजय निरूपम: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज जो देश में स्टील की डंपिंग हो रही है और मुनाफा घट गया है, प्लांट ओवर-रन हो गए हैं, तो क्या यह सारा नयी पालिसी आने के बाद हुआ है? क्या इस पॉलिसी पर मिनिस्ट्री पुनर्विचार करके कोई ऐसे कदम उठाएगी कि ये जो स्टील इंडस्ट्री है, जो अभी घाटे में जा रही है, उसको हम बचा सकें? क्या मिनिस्टर साहब ऐसा कोई ऐश्योरेंस देंगे कि इस पर पूरी तरह से विचार करके या योजना बनाकर आगे चलना चाहिए?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मूल सवाल सेल के इंवेंट्री से जुड़ा हुआ था। तकरीबन 10 से 14 लाख टन स्टील सेल में पड़ा हुआ था। मेरे सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने उस दिन बताया था कि पिछले तीन महीने में सेल का सेल बढ़ा है और इंवेंट्री कम हुई है। जिस प्रश्न पर हाफ-एन-आंवर की नोटिस आई उसमें मेरा प्रश्न यही था कि किस शर्त पर इंवेंट्री कम हुई है। पिछले माह में स्टील बेचा गया, वह किस कीमत पर बेचा गया, कितने क्रेडिट पर बेचा गया और किन पार्टियों को बेचा गया? मेरा सवाल यह था। मंत्री जी, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। मैंने यह पूछा था कि तकरीबन एक हजार करोड़ के आसपास अन-सिक्योर्ड क्रेडिट सेल का पड़ा हुआ है। उस क्रेडिट की वसूली के लिए मिनिस्ट्री क्या कर रही है, सेल क्या कर रहा है? कभी वह वसूली होगी या नहीं होगी और यदि होगी तो कब तक होगी? उतना बड़ा एमाउंट अन-सिक्योर्ड क्रेडिट के तौर पर छोड़ दिया गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है इसकी छानबीन होनी चाहिए। महोदय, सेल की इवेंट्री चूंकि बढ़ रही थी इसलिए प्रोफिट कम हो गया और प्रोफिट कम होने के कई कारण थे उसमें से एक कारण था-प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा रहा था। हाई प्रौडक्शन कॉस्ट के कई कारण थे उसमें से एक कारण मेरा मानना है कि वह कौल इंपोर्ट रहा है। सेल तकरीबन 60 से 80 लाख टन कोल हर साल इंपोर्ट करता है। एक हजार से डेढ़ हजार करोड़ रुपए तक इंपोर्ट हो रहा है। अक्सर इंपोर्ट में किकबैक होता है, मुझे उस डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन जब-जब हमने अपनी स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों नहीं रोक रहे हैं तो हमेशा सेल की ऑथोरिटी की तरफ से, आफिशियल की तरफ से इंपोर्ट करने पर जोर दिया गया इसलिए मुझे शक हो रहा है। मैं नहीं मानता कि जो कुकिंग कौल सेल को यहां चाहिए वह हिन्दुस्तान में उपलब्ध नहीं है। फर्क सिर्फ आँश् कंटेंट का है। मैंने हमेशा अपनी मीटिंग में कहा कि अगर आँश् ज्यादा है तो उसको कम किया जा सकता है, उसके लिए हमारे देश में वाश रज उपलब्ध है। हमारे यहां कोल माईन के पास वाशरीज हैं, उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। तो वाशरीज के उपयोग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है, मंत्री महोदय, यह बताने की कोशिश करें? महोदय, कौल इंपोर्टर के संदर्भ में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा सेल आस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करता है और आस्ट्रेलिया दुनियां का सबसे बड़ा कौल इंपोर्टर है। उसी तरह इस दुनियां का सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर जापान है और आस्ट्रेलिया से जापान हर साल तकरीबन 80 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करता है इसलिए आस्ट्रेलिया उसी प्राईस पर बाकी देशों को भी कौल देता है जिस प्राईस पर वह जापान को कोल देता है। इस प्राइस का नाम है-जे०एस०एम०, जापानीज स्टील मिल प्राइस। सेल कहता है कि हम जे०एस०एम० प्राईस पर कोल इंपोर्ट करते हैं। मगर जे०एस०एम० प्राइस पर भी बहुत बड़ा घपला हो रहा है। मैं उस घपले की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जापानी लोग बड़े होशियार व्यापारी होते है। जापानी क्या करते हैं कि सार्वजनिक उद्देश्य से एक एग्रीमेंट बनाते है और एक अपने मतलब का एग्रीमेंट बना लेते है। निजी उद्देश्य से। एक एग्रीमेंट पब्लिक होता है दूसरा एग्रीमेंट सीक्रेट होता है। तो जो पब्लिक एग्रीमेंट है उसके हिसाब से प्राइस फिक्स होती है और जो प्राईवेट एग्रीमेंट है उसके हिसाब से प्राईवेट प्राइस फिक्स हो जाती है तो जापानियों को जो आस्ट्रेलियन कम्पनी कोल देती है उसकी एक अलग प्राइस होती है और दुनियां भर में दिखाने के लिए अलग प्राइस होती है और हमारे यहां जे०एस०एम० के अंदर जो पब्लिक प्राइस है उस प्राइस पर कोल इंपोर्ट हो रहा है, यह मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। मेरा आज एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था। उस पर मंत्री महोदय का जवाब आया है। मैंने पूछा था कि आखिर किस प्राइस पर आप कोल इंपोर्ट कर रहे हैं? तो बताया गया कि 53.40 यू.एस. डॉलर पर मैट्रिक टन जे.एस.एम. प्राइस का जो प्राईवेट प्राइस है, प्राईवेट सैक्टर का जो प्राइस है। जापान जो अपने लिए जिस प्राइस पर कौल इंपोर्ट करता है वह तकरीबन 45 से 50 डॉलर पर मैट्रिक टन के आसपास होता है, यानी पब्लिक और प्राईवेट प्राइस में 5 डॉलर पर टन का फर्क होता है। यह मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। सेल 60 लाख टन कोल हर साल इंपोर्ट कर रहा है। 60 लाख टन के हिसाब से अगर 5 डॉलर पर टन इधर-उधर हो रहा है तो तकरीबन 300 लाख डॉलर का नुकसान सेल को पहुंचा रहा है। पिछले 5 सालों में 1500 लाख डॉलर का नुकसान हो चुका है।

मैं यह बताना चाहता हूं मंत्री महोदय को, पता नहीं अभी तो नए आए हैं मंत्री जी, उन्होंने कहा भी कि मैं नया हूं। तो मुझे मंत्री जी के प्रति बड़ी सहानुभूति है, सचमुच बहुत सिम्पेथी है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में तकरीबन 1500 लाख डॉलर का नुकसान हो चुका है सिर्फ कोल इम्पोर्ट के नाम पर। अगर हम किक बैक की बात करें तो आप अभी-अभी आए हैं मंत्रालय में लेकिन में बता दूं मेरे पास एक जानकारी है कि कोल इम्पोर्ट में जो किक बैक होता है, तकरीबन 5 डॉलर प्रति टन के हिसाब से किक बैक दिया जाता है और वह आंकड़ा भी 1500 लाख डॉलर के आसपास चला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह पैसा कौन खा रहा है? यह पैसा कब तक खाया जाता रहेगा? मैं यही तो मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मुझे बताया जाए कि सेल के अंदर एक इनक्वायरी सेटअप की जाए कि सेल में सेल के अधिकारियों या किसी भी संख्या के साथ .....(व्यवधान)....

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Vice-Chairman, this is a serious allegation. The Government should inquire into it. Crores and croers of rupees are involved.

SHRI SANJAY NIRUPAM: Let the Minister reply. That is why I am putting this question to the Minister.

कि यह पैसा कौन खा रहा है? कब तक खाएगा और मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कोल डील जो हुई, उसकी सी.बी.आई. से इनक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आज भी अनस्टार्ड क्वेश्चन था, उसका भी जवाब मंत्री महोदय ने दियां मैंने पूछा था कि सी.बी.आई. ने तकरीबन एक साल पहले कोल डील पर सवाल उठाते हुए एक पत्र भेजा था सेल अथॉरिटी के पास।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप कोल से स्टील में चले जाएंगे तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है.... (व्यवधान).....

श्री संजय निरूपम: सर, यह सही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्योंकि कोल इम्पोर्ट कर रहा है और कोल इम्पोर्ट करने में बहुत बड़ी रकम का नुकसान हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): यह हाफ एन ऑवर डिसकशन है। आप अभी कोयला इम्पोर्ट करेंगे, फिर कोयला जलाएंगे, फिर कुछ और करेंगे..... (व्यवधान).....

श्री संजय निरूपम: मैं उतना कुछ नहीं करूंगा। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सी.बी.आई. इनक्वायरी के लिए एक पत्र भेजा गया था, वह पत्र कहां है? मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा कोई पत्र नहीं आया लेकिन मैं मंत्री महोदय को पिछले साल के न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस बहुत भरोसेमंद न्यूज़पेपर है। उसमें लिखा है कि- The Steel Authority of India has reported that they saw a sharp fall in profits for 1996-97; in a sliggish market it is now plagued by inquiries launched by the CBI and the Vigilance Cell against at least six of its top officials."

मंत्री महोदय का जवाब आया है कि ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। मैं अगर चाहूं तो प्रिविलेज नोटिस मूव कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा हूं। शायद इनको भी घुमा दिया गया होगा यानि सेल में इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सी.बी.आई. का वह पत्र कहां है, उस पत्र के बारे में बताया जाए। सेल ने कहा है कि पिछले तीन महीने में हमारी सेल्स बढ़ी है। पिछले तीन महीने में प्रॉफिट कितना बढ़ा है, यह नहीं बताया जा रहा है। इन्होंने सेबी को एक पत्र लिख कर बताया है कि अभी हम आपको प्रॉफिट नहीं बता सकते। क्या मजबूरी है? जबकि एक परंपरा भी है कि हर तीन महीने का जो आपका प्रॉफिट है, वह सेबी को बताना है, टोटल खर्चा बताना है। उस रिपोर्ट से मैं बता रहा हूं- The Steel Authority of India Ltd., has expressed its inability to declare its first quarter financial results due to certain operational difficulties." ये डिफिकल्टीज़ क्या है? क्यों छिपाया जा रहा है इनको? मंत्री महोदय अगर आज यह सदन में बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी कि पिछले तीन महीने में आखिर कितना प्रॉफिट हुआ और टोटल रिज़ल्ट क्या रहा है? अगर छिपाया जा रहा है तो क्यों छिपाया जा रहा है?

इसी से जुड़े हुए एक-दो प्वाइंट और रखना चाहता हूं कि सेल पर लगातार कर्ज़ का बोझ बढ़ता जा रहा है। मैं लेकर आया हूं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो सर्वे रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हिसाब से तीन साल पहले फॉरेन डेट जो हमारे यहां था, जो विदेशी कर्ज़ा सेल के ऊपर था, वह 20 हज़ार करोड़ के आसपास था। तीन साल पहले 20 हज़ार करोड़ था, एक साल बाद घट कर 19 हज़ार करोड़ होता है और पिछले साल यह कर्ज़ा बढ़ कर 22 हज़ार

करोड़ हो जाता है। ये विदेशी कर्ज़ की हालत है, जो छोटे-मोटे डेटर्स होते हैं, उनका कर्ज़ा भी बढ़ता जा रहा है। 16 हज़ार करोड़ तीन साल पहले था, दो साल पहले 19 हज़ार करोड़ हो गया और पिछले साल 20 हज़ार करोड़ हो गया यानि कर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है सेल के ऊपर। 15 हज़ार करोड़ रुपए सेल सिर्फ अपने कर्ज़ पर बतौर इंटरेस्ट पे कर रहा है हर साल। मैं पूछना चाहता हूं कि सेल की डेट ईक्विटी रेशियो क्या है? मैं बता दूंगा उसमें एक प्वाइंट जोड़ते हुए मेरी जानकारी है कि 2.5 रेशियो उनकी डेट ईक्विटी शेयर हो गई है। आम तौर पर जो कॉमर्स के जानकर होते हैं, जो फाइनेंशियल लाईन के लोग होते हैं, उनको जानकारी होगी कि 2.1 तक तो बरदाश्त किया जा सकता है जिस कंपनी की डेट ईक्विटी रेशियो ....(**व्यवधान**).....

SHRI JIBON ROY: Mr. Vice-Chairman, Sir, if the House agrees, let there be a discussion on the working of the Ministry of Steel Industry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The Chairman has permitted this Half-an-Hour Discussion.

SHRI JIBON ROY: The scope of this discussion is being widened and widened.

So, I suggest let there be a full-fledged discussion on the working of the Ministry of Steel Industry.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): स्टील के मामले पर सवाल है.....(**व्यवधान**).....प्लीज कम टू दी प्वाइंट.

श्री संजय निरूपम: अंत में सर, एक दो सवाल और रह गये हैं। सेल में पिछले कुछ दो सालों में 20 हजार करोड़ रुपये माडर्नाइज़ेशन के नाम पर खर्च किये गये। 20 हजार करोड़ रुपये सैल ने अपने डिफरेंट स्टील प्लांट्स के....(**व्यवधान**).....

SHRI SANJAY NIRUPAM: Mr. Roy, this question is very much related to SAIL.

SHRI JIBON ROY: It is not SAIL. Your original question was stockpiling. Now, you are going.....(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Don't do so much of stockpiling, Mr. Nirupam. (*Interruptions*).

श्री राजू भाई ए॰ परमार: हमारे संजय निरूपम जी इतने अच्छे ईशूज स्टील मिनिस्टरी के ला रहे हैं, उनको बोलने दिया जाए। ....(**व्यवधान**).....वह इतने अच्छे प्वाइंट्स ला रहे हैं, इसमें क्या गलती है?..... (**व्यवधान**).....

श्री संजय निरूपम: कृपया मुझे बोलने दीजिए।

SHRI JIBON ROY: Sir, it cannot take place like this. If modernisation has to be discussed, if the entire SAIL is to be discussed, we also want to speak something.

SHRI SANJAY NIRUPAM: Then, why did you discuss Durgapur?

SHRI JIBON ROY: We have limited ourselves only to marketing. (*Interruptions*). If it is to be discussed, it is good. Time should be given to all and it should be on the agenda.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Roy, you have had your chance. You have put your questions. Please allow him now.

श्री संजय निरूपम: महोदय, मेरा कहना है कि सेल ने पिछले दो-तीन सालों में 20 हजार करोड़ रुपये माडर्नाइज़ेशन के नाम पर खर्च किये। आम तौर पर एक मान्यता है कि किसी भी स्टील प्लांट पर अगर तीन हजार करोड़ रूपये खर्च करें और स्टील प्लांट इस्टैब्लिश किया जाए तो उससे कम से कम एक मिलियन टन का प्रोडक्शन हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करके सेल ने अपनी प्रोडक्शन में कितने मिलियन टन स्टील पिछले तीन-चार सालों में बढ़ाया है? अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं 20 हजार करोड़ रुपये में कुछ गड़बड़ हुई है। महोदय, मैं बता रहा था कि कर्जा अनप्लान्ड था, उसी तरह से खर्च भी अनप्लान्ड हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सेल की मार्किटिंग स्ट्रैटली तय करने के लिए सेल के चेयरमैन और उनके कुछ साथियों ने मनाली में मीटिंग की और उस मीटिंग के लिए सेल के दो प्लेन गये, लोग अपनी फैमिली के साथ वहां गये। मार्किटिंग स्ट्रैटजी तय करने के लिए हिल स्टेशन पर जाने का क्या मतलब था? यह सेल का खर्चा बढ़ाने का, अनप्लान्ड खर्चा बढ़ाने का एक छोटा सबूत है। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि सेल को आटोनॉमी के नाम पर खुला छोड़ दिया गया है, अब मंत्रालय उसमें इंटरफीयर करे, कहीं न कहीं उसके अंदर दखलअंदाजी दे और उसकी दशा को और बिगड़ने से रोके। सेल का प्रॉफिट घटता जा रहा है। जाहिर है कि सेल के टॉप ऑफिशियल्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। सेल के टॉप ऑफिशियल्स के खिलाफ

बिल्कुल तत्काल इन्क्वायरी सैटअप की जाए और जो कोल डील हो रही है, इसमें हजारों करोड़ रुपये की बर्बादी अब तक हो चुकी है। उस कोल डील की सी.बी.आई. से इन्क्वायरी कराई जाए ताकि सेल जो हमारी दुनिया की कुछ वन ऑफ दी बैस्ट यूनिट्स में से थी, उस सेल को डूबने से, बर्बाद होने से बचाया जा सके।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (West Bengal) Mr. Vice-Chairman, Sir, I understand the limitations of the scope of the disucussion. But since a number of issues have been raised, they need to be responded to. The issue was the large-scale increase in the volume of inventory, the question was why steel remained unsold in the country. One of the basic factors could be the economic recession that is going on. That is true. But it is also true that steel is being dumped in India. No steps are being taken. Steel is being dumped in India because recession is there all over the world. Therefore, in order to improve the situation, effective measures should have been taken by the Ministry of Steel to impress upon the Government of India that the Government of India needs to do a little more than what it is doing to protect the steel industry. I must say the Steel Ministry has not succeeded in the job. The Steel Ministry has failed to initiate effective anti-dumpting measures. Thirdly, I can say, Sir, that if the steel industry in India depends on the export market, there are bound to be greater shocks because in the world as a whole, because of the economic condition that is prevailing at the moment, the demand for steel is sharply going down. There is unsold stock everywhere. Therefore, if you depend on the external market, I do not think you will be able to survive; neither will you be able to reduce the inventory.

Therefore, the most important and effective strategy will be to explore the domestic market and in order to explore the domestic market, the Steel Authority of India needs to change its marketing policy sharply. While discussing the marketing policy, it is obvious that you should commend the way in which the Steel Authority of India is functioning. Something is wrong with the Steel Authority of India, something is wrong with steel, and if the wrong is not remedied, I don't think that the things will improve. Who are the people who are running the Steel Authority of India? Who are the people who are making the policy? Who are the people who are initiating the steel revival strategy and the marketing tactics? Who are these people? There is enough scope for improvement. But it is not being done. There is an apprehension which has been expressed by my hon. colleagues. They have said that there is an element of corruption, there is an element of irregularity, there is somebody in the Steel Ministry who is not performing his job. That is very clear. Somebody in the SAIL or some people in the SAIL are not performing their jobs. They have everything else to do than to do service to the Steel Authority of India. The hon. Minister must look into this thing very scrupulously. Sir, I don't agree with the hon. Steel Minister when he said that there is monitoring at five different levels. If there is monitoring at five different levels, then I must say that there is no monitoring at all. Who is going to monitor the Steel Authority of India? The SAIL Authority is monitoring after three months, the Minister is monitoring after six months and the Prime Minister is monitoring after one year. Therefore, the effective system of monitoring ....*(Interruptions)*

SHRI NAVEEN PATNAIK: It is being done on quarterly basis.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: There has to be a nodal agency to monitor the performance of the Steel Authority of India, of the different units, of the sale division, of the raw-material division, and of the purchase division. Steel is being sold out at discounted price. That is where the apprehension lies. Why is the price of steel being discounted? While discounting the price of steel, do you take into consideration the minimum cost of production; the minimum profit or is the discounting policy arbitrary? This is a very important question as to how steel is being discounted and whether you are selling steel on credit. If you are selling steel on credit, now do you realise the money and at what point of time? What is the difference? Therefore, there was a big apprehension that in order to show that the inventory had been reduced, there was something wrong in the

accounting system, there are something wrong in the SAIL, not steel but the SAIL. Something is wrong in the way it is being sold on credit. The hon. Minister must explain this thing. How is that policy determined and who is determining that policy? While saying so, I must say that low productivity is a problem and low productivity is a problem because the technological upgradation that has been done, is not up to the standard. The hon. Minister must answer this question. When the modernisation was done, there had been cost overrun and time overrun might have been beyond the control of the Minister. But the point remains is whether the technological level which was supposed to be attained after the technological upgradation, was attained or not. What was the percentage? If the technological upgradation which was expected had not been attained, then who was responsible for that? Who were the people who had been doing the technological upgradation? Who were the contractors? Why was it not done? You have inherited bad steel. But since you have inherited it, it is obligatory on your part to explain this thing. Whatever you might have inherited, you are in the process of continuous governance. You cannot pass on the buck to somebody else. The Ministers might have changed but the Ministry did not change. The Steel Authority of India did not change, the Chairman did not changge. Therefore, a deep study has to be made whether the modernisation has really improved the productivity level and has brought it to the level which was expected. If it had not, what were nat reasons? While saying so, I take this opportunity to raise one important issue about the IISCO because the total production of the Steel Authority of India depends on its units.

The Government had been sitting on the question of modernisation of IISCO for a long time. I have reason to believe that the Steel Authority of India is not interested in modernising IISCO deliberately; they are putting forward an abnormal, unrealistic and overvalued modernisation scheme. According to the SAIL management, 4,000 crores of rupees are required for that purpose. But I have reason to believe that the local management has put forward a proposal which states that IISCO can be modernised with only 400 crores of rupees. I believe that somebody a very important person, in the Steel Ministry — he may be the Secretary or somebody else — might have approved it, but the Chairman of SAIL stands in the way because he would like to use the modernisation question to clean the balance-sheet of SAIL. The Minister owes an explanation, whether he has received any modernisation scheme from the management, whether he has looked into it, whether the SAIL officials have looked into it and why the SAIL authority or the SAIL Chairman stands in the way. And if the SAIL authorities are allowed to work and move according to their own sweet will, if they are allowed to be more important than the Minister himself, — and in some cases they believe that they are so; they are having larger than life perception about themselves - if this is allowed to continue, then the functioning of SAIL will not improve, the functioning of the Steel Ministry will not improve, and the biggest public sector of the country will turn sick. That is the apprehension we are having. We must know from them what the realisationship is, what the functional relationship between SAIL and the Steel Ministry is and who are looking after that and whether the people who are there believe that they can do what they want. Sir, while saying so, I implore the Minister to look into the allegations that have been raised here. Since the allegations have been raised here regarding the purchase of coal and the amount that is exchanging hands, it is too serious to overlook them. He should promise to hold an inquiry on the question of coal purchase. That is number one. Number two, I believe that the hon. Minister will assure the House that something more will be done, much more than what is being done now, to improve the functioning of the Steel Ministry. Thirdly, he must tell the House what is being done to modernise IISCO and what stands in the way. Thank you, Sir.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, knowing my limitations about the steel inventory, not only in SAIL but in most of the steel mills in the country, I will just ask a few pointed questions. A lot of points have already been

discussed. Does the hon. Minister know that the cost of production of steel in our country is around 260 dollars per tonne, whereas the average cost of production in the world is 230 dollars. The most interesting part, Mr. Vice-Chairman is that one Indian - the group is known as ISPAT - is buying steel mills all over the world and they are reducing the cost to 180 dollars! Would the Minister like to make use of the expertise, and advice of that Indian, who is doing that, so that our steel can also cost 180 dollars per tonne? Then the question of marketing all over the world will not be problem.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Do you want Mr. Mittal to take over it?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I have not said, Mr. Gurudas Das Gupta - I know what your attitude is; that is why our industry is suffering - I have never said, "Mittal wants to take over". Do you want to put words into my mouth. Please don't do that. I have only said, "Would you like to take suggestions?" I am suggesting something. You have also suggested something. Do I not have the privilege, Sir, to even suggest something good for the country? Is Mittal an outsider? Is he an 'anti-national'? Is Mittal somebody who should not be talked about? Simply because he is a successful businessman, has he become an unwanted man? If he can help the Minister, if he can help the country, we must take his help. I have only suggested this. If you don't want his help, the steel industry will go further down. Let me tell you this. Please change your attitude, if you want this country to improve.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, I have only sought a clarification whether he wanted Mr. Mittal to take over as Chairman of the SAIL.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, he is a good friend of mine. He has put this question to me. So, I thought I should tell him all these things.

The second point is that dumping has been discussed quite often. Most of the speakers have talked about dumping. As far as dumping is concerned, I think our Minister can on his own do nothing. I think in the Commerce Ministry there is a department. There is a committee which decides about dumping. Will the hon. Minister make efforts to approach this committee so that the dumping is proved? There is a long procedure for this. Will the Minister take up the matter with the Commerce Ministry and also ensure that a dumping duty is put by the Commerce Ministry? The developed countries including the USA are controlling the freight rates in the world. The steel which goes from India to the USA, costs nearly double, if the same steel comes from the USA to India. If that is so, what are the steps that our Minister is planning to take to check this anomaly? Otherwise, our steel will always be expensive in the world market.

The next question is this. It is very nice to listen to the hon. Minister talking about infrastructure development. We have seen the Budget just now. There is hardly any investment in the infrastructure sector. It has been suggested that we would depend on the private sector. We depend on the private sector and we don't approve the projects like the airport in Bangalore! I don't know what approvals are given in the country. He is saying that all the steel will be used for infrastructure development. Could I know what kind of infrastructure is being developed? What are the plans? What are the sanctions either to the public sector or to the private sector? It is all in the air. Maybe, in the next two or three years there will be no sanctions, the steel will be accumulated and we will not have any place to keep the steel. We will have to close the factories. This is not a public forum. This is a very serious place to discuss. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, what the kind of infrastructure is that he knows about. How much quantity of steel does he imagine will be consumed by the infrastructure sector in the next two or three years?

Coming to exports, I have already stated what the costs are. The hon. Minister has mentioned that we are importing 1.5 million tonnes. I am only going by the existing figures. I am not questioning him. I am not doubting him. We are exporting three million tonnes. It sounds very good. But can he tell us what the total value of three million tonnes is? What

is the value of 1.5 million tonnes? Actually we are exporting at a much lesser price, whereas we are buying at a higher price. Still it is lesser in our country. The hon. Minister can give the figures. I understand that the exports from our country, whatever goes from the SAIL, are going at a heavy loss. Finally, the export losses are being adjusted against the profits made in India by the SAIL, whatever the SAIL can sell in India.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Vice-Chairman, Sir, there are some complaints. I would like to know from the hon. Minister, the SAIL being a public sector, whether the Government is itself patronising the SAIL. Over a year-and-a-half we have been hearing from the Railway Minister that the steel used for making coaches and wagons is substandard. I think a pretext was made by the Government of India, by the Ministry, to give the quotations and tenders to foreign parties. If that is so, what steps is the Government taking to improve the quality of our steel? We say that our coal is drift coal and it contains 40% fly ash. We have got 40% fly ash. Therefore, we imported from Australia at an exorbitant rate by draining the foreign exchange.

[7.00 P.M.]

At the same time, to earn foreign exchange, they have reduced the price of steel and brought it at the level of international market price. Why don't they sell the same steel domestically at a little less price? Is there any anomaly in prices in the name of competing internationally? We cannot compete internationally because our own public sector undertakings and the Government Departments say that our steel is substandard. Can't we sell steel in the Indian market by reducing the price, if not at the international price, a little lower than the market price in our country? For the last two years there is no stable Government. Most of the infrastructure projects started by the Government have come to a standstill. That is why there is recessing in the market. So I would like to know from the hon. Minister what the percentage of decline in consumption of steel is in our country. I would also like to know whether there are any projects at a standstill. That may be the cause of stockpiling of steel at the steel stockyards. If that is so, will the Government sell steel domestically by reducing the price to the level of international market price?

Thank you.

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। बहुत सारी बातें कही गयी हैं जिसमें करप्शन की बातें भी आई हैं। मैंने उस विषय को ज्यादा हाथ नहीं लगाया था इसलिए कि शायद आज इस अवसर पर उचित नहीं होगा क्योंकि चर्चा आ चुकी है इसलिए मैं एक तथ्य और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं जिसकी मुझे जानकारी है। वह यह है कि 135 करोड़ रुपया किसी स्टील फैक्ट्री के काम करने वाले एक कंट्रैक्टर को दिया गया। उस 135 करोड़ रुपए में से कोई काम नहीं हुआ है। वह 135 का 135 करोड़ रुपया डूब खाते में है। जिस तरह से 135 करोड़ रुपया यूरिया में चला गया है एडवांस देकर। आज तक यूरिया का एक टन माल नहीं आया। 135 करोड़ रुपए का यह विषय भी मुझे लगता है कि यूरिया की तरह ही बनने वाला है। माननीय मंत्री जी अपने विभाग से इसके बारे में जानकारी करें। अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि जितने प्वाइंट्स हमने आपके सामने विचार के लिए रखे ...(**व्यवधान**)

SHRI NAVEEN PATNAIK: Was it done at the time of our Government or some other Government (*Interruptions*).

SHRI JOHN F. FERNANDES: Is he talking about the Indian Government or a foreign Government? (*Interruptions*)

श्री रामदास अग्रवाल: यह ठीक है कहना आपका। बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट तो कन्टीनुएंस में है। लेकिन ये जितने काले कारनामे किए गए हैं उनमें यह शामिल नहीं है। इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है .. (**व्यवधान**)

श्री संतोष बागडोदिया: फिर आप बैठाइए न कमेटी। हिम्मत हो तो कमेटी बैठाइए। जिसने किया वह फंसेगा। वह तो हिम्मत है नहीं ...(**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल: हम वही तो कह रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आग्रहपूर्वक ...(**व्यवधान**)

श्री संतोष बागडोदिया: अभी आप लोग दोष देते हैं पहले वालों को। हिम्मत नहीं है आपको कमेटी बैठाने की ...(**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल: हमें कोई न कोई इंक्वायरी बैठानी चाहिए ...(**व्यवधान**)

श्री संतोष बागडोदिया: आपको हिम्मत है तो कमेटी बैठाइए ...(व्यवधान) आज तो आपके पास फाइलें हैं, रिकार्ड है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): और कोई सवाल नहीं। अब मंत्री जी बोलेंगे। जवाब देंगे।

श्री संजय निरूपम: इसके लिए हाउस कमेटी बनानी चाहिए।

श्री रामदास अग्रवाल: किसी न किसी रूप में इसकी जांच होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य: होनी चाहिए हमें मंजूर है ... (व्यवधान)

श्री रामदास अग्रवाल: हमें इस तरह से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारी बातें गुरुदास जी ने भी उठायीं और उन्होंने भी उठायीं ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): जवाब तो सुन लीजिए उनको। जवाब सुनने से पहले आप क्यों फैसला ले रहे हैं। मिस्टर मिनिस्टर।

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, I will first talk about the question of dumping which was referred to by several hon. Members. It is a fact that steel is being dumped in India by some of the CIS countries especially Ukraine, Kazakhstan and Russia. An anti-dumping petition has also been filed by major steel producers with the Designated Authority in the Ministry of Commerce, under the Customs Tariff Act. There have also been reports of dumping from South East Asian countries which are presently in the grip of currency crisis, including Indonesia and Korea. The products being dumped are mostly hot rolled (HR) coils, sheets and skelp.

The anti-dumping petition was filed in January, 1997 against imported HR coils and sheets by M/s Essar & Lloyd Steel, supported by SAIL and Tisco, after which the Designated Authority has been conducting investigations in the matter. Soon after filing of the petition, the Ministry of Steel had taken up the matter with the Ministry of Commerce to expedite the investigations with a view to levying provisional antidumping duty on these products.

The Ministry of Steel has also urged upon steel producers to furnish all relevant data required for investigations so that the findings could be finalised quickly by the Designated Authority. The Steel Ministry has been actively monitoring the progress of investigations and interacting with the Commerce Ministry on these issues at the highest levels. Recently, I also urged upon the Commerce Minister to finalise the findings. In its interim findings based on the *preliminary investigations, the Designated* Authority has concluded that there is injury to the domestic industry due to increase in imports of these iron and steel items. It has also been concluded that dumping is taking place from these countries in India. However, the third element required for levying of anti-dumping duty, that is causal link with the injury to the domestic industry taking place as a result of dumping from these countries has not yet been established. Therefore, investigations are still continuing and no provisional anti-dumping duty has been levied so far. In the meeting between the Commerce Minister and myself on 14th of this month, wherein a number of Chief Executives of steel producing units of the country were also present, I urged upon him that the anti-dumping duty on imported HR coils/sheets should be levied quickly.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) in the Chair. It is, therefore, evident that the Ministry of Steel is alert to the progress of the anti-dumping case and is monitoring the same closely. Under the Customs Tariff Act and the anti-dumping rules framed in line with the WTO rules and regulations, adequate provisions exist to stop any dumping of materials by foreign countries in India. I had, in a recent meeting with the Commerce Minister, also stressed the need for strengthening of the anti-dumping machinery in the country so as to make it responsive and quick in acting against dumped imports.

Sir, in reply to some of the other questions posed by the hon. Members, as far as exports are concerned, which the hon. Member from the Opposition wanted to know, in 1997-98, despite a sluggish market, we exported an all time high of more than 3 million tonnes and earned a recored figure of approximately Rs. 2,900 crores overtaking sectors like electronics and manmade fabrics.

Sir, a number of Members have been concerned about certain enquiries made in the Steel Ministry. As I said, the Auditor General's Report on the Durgapur Steel Plant has been laid in both the Houses of Parliament. It has been laid in this Session only. There were certain references which came from different people. One reference came from Mr. Chitrasen Sinku, a Member of the Lok Sabha. This reference was received in February, 1997. This deals with production of hot metals, crude steel and saleable steel much below the plant production in the Rourkela Steel Plant. As regards the action taken, the points raised by the Member were responded to by the then Steel Minister in October, 1997 that is, by the Steel Minister before my time. Sir, another complaint has come from Shri R.K. Samantrai, Joint Secretary of the Rourkela Mazdoor Sabha. This reference was received in May, 1998. It relates to poor performance of the Rourkela Steel Plant, financial and technological bungling in modernisation of that plant.

Comments were sought from SAIL in June, 1998. The third reference was from Shri Rama Panda, District Coordinator, Biju Janata Dal, Sundergargh. The reference was received in May, 1998. It was regarding shifting of the Raw Materials Division Headquarters from Calcutta to Orissa and for investigation into the malpractices in Rourkela Steel Plant modernisation. Comments were sought from SAIL in June, 1998. The fourth reference was from the equity shareholders of Rourkela Steel Plant. It was received in May, 1998. The points raised were, impecunious and pernicious consultancy services of M/s. M.N. Dastur & Co. in Rourkela Steel Plant modernisation, failure of Silicon Steel Plant to produce CRGO and the rebuilding of Coke Oven Batteries within a particular period. Comments were sought from SAIL in June, 1998.

Sir, recently there has been a CBI inquiry going on in small works in the Rourkela Steel Plant. The report is not with us yet. It is not proper for me, therefore, to comment on that. Many hon. Members have spoken about various inquiries and various subjects pertaining to SAIL and other parts in the steel sector. I would be more than glad to receive their letters regarding these and I will look into them very closely.

Another question that was raised by an hon. Member was regarding IISCO. I would like to explain, if I may be allowed to speak on that. Sir, as we all know, the Indian Iron and Steel Co. Ltd. was taken over by the Government by three successive Acts of Parliament — the Acts of 1972, 1976 and 1978 respectively. And then the plant was handed over to SAIL. At the time of taking over also, the company was making losses. After taking over of the company, the Government has moved about ten proposals, including privatisation, for its modernisation and revival, which was felt to be imminent. Unfortunately, none of them could fruitify into an implementable package. In June, 1994, IISCO had to be referred to BIFR, when its networth got completely eroded.

Therefafter, in 1995 the Department requested the Government for budgetary support, which the Government did not find possible to grant. Subsequently, revival through joint venture with TPE of Russia was also considered but the same could not fruitify for lack of necessary inter-governmental agreement between the Russian federation and the Government of India for utilisation of monies in the Escrow account.

At present, the Government is considering a proposal for modernisation and revival of IISCO by funding through the Steel Development Fund, the SDF route. This proposal takes into account participation to the extent of Rs. 100 crores in the equity of IISCO by the Government of West Bengal. (*Interruptions*) Let me finish.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Let him finish first.

SHRI NAVEEN PATNAIK: An hon. Member of this august House says that a proposal can be there for IISCO's revival in approximately four hundred crores of rupees. I would be very glad naturally to look at that proposal and if it is practical, naturally it would be very good thing.

SHRI JIBON ROY: Sir, what is the real position of IISCO? Since you are answering, I am questioning you. What is the real position of IISCO now? Since long we have been

hearing that it is being done through the SDF route. Now, I have not raised this question. Since you are answering, I am questioning you. We want to know what the real position of IISCO is. Where do we stand now?

श्री संजय निरूपम: सर, मैंने इतने सवाल किए, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं आया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please sit down.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, he is referring to IISCO.

I am putting a question to him. Kindly give me an opportunity to put a question to the hon. Minister. I want to know whether it is true that the steel ...(*Interruptions*)...

SHRI RAMDAS AGARWAL: This is not the subject matter at all. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I am only suggesting if the authority of the IISCO has submitted a proposal, if the Department has received the proposal, then what is their reaction to that? He wants me to ...(*Interruptions*)... It is there in the Department. The proposal is lying there.

श्री संजय निरूपम: उपसभापति जी, ...(व्यवधान).

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप बैठिए, अभी। उनके बाद आप बोलिएगा। ...(व्यवधान)...

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, he can answer it. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय निरूपम: सर, मैंने जो सवाल उठाए थे, उनमें कम से कम पांच तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। अब इसमें से एक सवाल का जवाब भी मंत्री महोदय ने नहीं दिया बल्कि उल्टे यह कहा कि अगर आप किसी तरह की इन्क्वायरी करवाना चाहें तो लेटर लिखिए। मुझे लगता है, लेटर लिखने से तो ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमने यहां सदन में प्रश्न रखे हैं। इसलिए मंत्री महोदय उसका एक सीरियसली नोट लें और उसका इमीडिएटली एसोरेन्स दें कि हम एक इन्क्वारी सेटअप करेंगे। कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए। क्यों टाला जा रहा है इन सारी चीजों को? आखिर सेल के करप्शन को क्यों छुपाया जा रहा है? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप बैठिए। आप बैठिए, न ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम: उपसभाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि सेल के करप्शन को आखिर मंत्री महोदय क्यों छुपा रहे हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): The Minister is reacting to it.

SHRI NAVEEN PATNAIK: If I may be allowed to answer that question, I would like to assure the hon. Member that this Government has nothing to hide. This Government has come to power recently. We have inherited certain problems. If appropriate complaints come, of course, we will look into them. If the reasons are strong enough, obviously, the appropriate stringent inquiry and action will be taken.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, could you direct the Minister...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): No, no.

SHRI SANTHOS BAGRODIA: Sir, give me one second. My request is ... ...(*Interruptions*)...

श्री संजय निरूपम: सर, मुझे लगता है, यह प्रश्न आधे घंटे के लिए नहीं है, कम से कम ढाई घंटे के लिए इस प्रश्न पर डिसक्शन होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप बैठिए। बोलिए, मिनिस्टर साहब। ...(व्यवधान)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, one second only. The hon. Minister has himself suggested that we can write letters. I will request that we have already raised the points here. If he cannot reply right now, we can appreciate his difficulty, let him reply to each Member, based on the points raised, instead of asking us to further write letters. please direct him to do that. ... (*Interruptions*)

SHRI RAMDAS AGARWAL: It is not possible for the Minister to reply to each and every point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Minister, do you want to say anything?

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, both the hon. Members have raised questions about IISCO. In fact, all the Members have raised questions about IISCO. ...(*Interruptions*)... It is the demand of the entire House and my demand too.

Some Members have kindly come to the Steel Ministry, to the office... ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): No, no. That is not the answer.

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, मंत्री जी लैटर मांग रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम: सर, पूरे विषय की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है और टाला जा रहा है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप बैठिए तो। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम: यह गलत हो रहा है। एकदम अन्याय हो रहा है हमारे साथ। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): अन्याय नहीं हो रहा। मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठिए तो। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम: इस आधे घंटे के डिसकशन का महत्व ही क्या रहता है, अगर मंत्री महोदय हमारे सवालों को गंभीरता से नहीं ले सकते? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप बैठिए, न। बैठिए, प्लीज। मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं बोलता हूं। ...(व्यवधान)... आप बैठिए तो। ...(व्यवधान)...

Mr. Minister, Please take your seat first. The Members of Parliament cannot go to your Ministry. That is not the system here. The system, is, you have to answer questions. ...(*Interruptions*)...

SHRI SANJAY NIRUPAM: And he is not answering our questions.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप फिर क्यों उठ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

The House is adjourned till 11 a.m. on Tuesday, the 28th July, 1998.

The House then adjourned at nineteen minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 28th July, 1998.